

भारत में मुद्रास्फीति का गतिशास्त्र : मुद्दे और चिंताएं *

दीपक मोहंती

सर्वप्रथम मैं बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने मुझे मुद्रास्फीति पर बोलने का यह अवसर प्रदान किया है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तात्कालिक चिंता का विषय है। पहले, मैं मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा और उसके बाद संक्षेप में मुद्रास्फीति की उन कीमतों का जिक्र करूंगा जो हमें चुकानी पड़ रही हैं। इसी क्रम में मैं मौजूदा मुद्रास्फीति के गतिशास्त्र का एक विश्लेषण भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अंत में मैं नीतिगत चिंताओं और सरोकारों का उल्लेख करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा।

मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां

इस बात को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि संसाधनों के इस्तेमाल के स्तर पर मंदी तथा स्थिर मुद्रास्फीति की संभावनाओं के फलस्वरूप 2010¹ में वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित किया जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान था कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2010 के दौरान 1.3 प्रतिशत तथा उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 6.2 प्रतिशत होगी। वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) मुद्रास्फीति जो जून-अगस्त 2009 के दौरान ऋणात्मक दायरे में थी वह तेजी से बढ़कर फरवरी 2010 तक 9.9 प्रतिशत हो गयी। उपभोक्ता मूल्यों में तो यह वृद्धि 14.9-16.9 प्रतिशत के घेरे में आ गई थी (सारणी 1)।

जहां तक थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति उपायों में अंतर का इस मुद्दा का संबंध है, मैं अपने इस भाषण² में उस पर गहराई से विश्लेषण करने का प्रस्ताव

¹ जनवरी 2010 अपडेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोश (आइएमएफ)।

² कृपया इसके विस्तृत विश्लेषण के लिए श्री दीपक मोहंती (2010) द्वारा 9 जनवरी को विकास अध्ययन केंद्र में तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय आय तथा संपदा में शोध के लिए भारतीय संघ के सम्मेलन में ‘‘भारत में मुद्रास्फीति के मापदंड: मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य’’ विषय पर दिया गया भाषण देखें।

* श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण, जो कि 4 मार्च 2010 को बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स में दिया गया। डॉ. ओ.पी. माल की उपस्थिति भी उल्लेखनीय है।

भाषण

भारत में मुद्रास्फीति का गतिशास्त्र : मुद्दे और चिंताएं दीपक मोहंती

सारणी 1: विभिन्न पण्य समूह की मुद्रास्फीति दर

(प्रतिशत)		
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ)	वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर	
	फरवरी 2009	फरवरी 2010
डब्ल्यूपीआइ - सभी पण्य	3.5	9.9
डब्ल्यूपीआइ - प्राथमिक वस्तुएं	6.9	15.5
डब्ल्यूपीआइ - खाद्य पदार्थ	9.4	17.8
डब्ल्यूपीआइ - ईंधन समूह	-3.4	10.2
डब्ल्यूपीआइ - विनिर्मित उत्पाद	4.8	7.4
डब्ल्यूपीआइ - विनिर्मित खाद्य उत्पाद	9.3	20.4
डब्ल्यूपीआइ - खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ उत्पादों छोड़कर	1.5	6.5
डब्ल्यूपीआइ - विनिर्मित उत्पादों, खाद्य पदार्थों को छोड़कर	3.8	4.3
डब्ल्यूपीआइ- आवश्यक पण्य *	10.5	21.6
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	फरवरी 2009	फरवरी 2010
सीपीआइ - औद्योगिक श्रमिक	9.6	14.9
सीपीआइ - कृषि श्रमिक	10.8	16.5
सीपीआइ - ग्रामीण श्रमिक	10.8	16.5
सीपीआइ - शहरी शारीरिक श्रम न करनेवाले कर्मचारी #	10.4	16.9
# : जनवरी से संबंधित		
* : डब्ल्यूपीआइ बास्केट में आवश्यक पण्यों में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलें, आलू, प्याज, दूध, मीठे पानी की मछली, मटन, मिर्ची (सूखी), चाय, कोफिंग कोयला, मिट्टी का तेल, आटा, चीनी, गुड, नामक, हायड्रोजेनेटेड वनस्पती, रेपसीड और सरसों का तेल, नरीयल तेल, मुंगफली तेल, लंबे वस्त्र/चादरे, धोती, साड़ी और महीन कपड़ा, घरेलू कपड़ों की साबुन और माचिसें शामिल हैं।		

नहीं करना चाहूंगा। फिर भी, मैं दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रथम, हालांकि मुद्रास्फीति की प्रतिशताओं में यह अंतर अतीत में भी रहे हैं फिर भी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई), औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू), सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डिफ्लेटर तथा निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) डिफ्लेटर औसतन लंबी समयावधि को देखा जाए तो वे सभी एक समान रहे हैं (सारणी 2)। द्वितीय, मुद्रास्फीति में इस मौजूदा अंतर का कारण मुख्य रूप से

सारणी 2: भारत में मुद्रास्फीति: मध्यम से दीर्घावधिक

(प्रतिशत)				
दशक	डब्ल्यू पीआई	सीपीआई- आइडब्ल्यू	जीडीपी अपस्फीति- कारक	पीएफसीई अपस्फीति- कारक
1	2	3	4	5
1951-52 से 1960-61	1.9	2.1	1.6	1.6
1961-62 से 1970-71	6.2	6.5	6.2	6.3
1971-72 से 1980-81	10.3	8.3	8.8	8.4
1981-82 से 1990-91	7.1	9.0	8.7	8.3
1991-92 से 2000-01	7.8	8.7	8.1	8.5
2001-02 से 2008-09	5.2	5.3	4.6	4.4
दीर्घावधि प्रवृत्ति	7.7	8.0	7.7	7.6
1971-72 से 2008-09 (दीर्घावधि 1951-52 से 2008-09)	(6.4)	(6.7)	(6.3)	(6.3)

डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई के अंतर्गत खाद्यवस्तुओं को दिए गए मूल्यांकनों में भिन्नता को ठहराया जा सकता है।

मुद्रास्फीति की लागतें

तथापि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसी भी रूप में भारत की मौजूदा मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊँची है। मुद्रास्फीति चिंता का विषय क्यों है? मुद्रास्फीति अपने साथ जुड़ी कीमतों के मद्देनजर सार्वजनिक नीति के सामने चिंता का कारण बनाई है विशेष रूप से तब जब हमारी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के पास मुद्रास्फीति से बचाव का कोई रास्ता नहीं है।

पहला, मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को क्षीण कर देती है। एक निश्चित आमदनी कमाने वालों और पेंशनभोगियों की खर्च करने वाली आय और उसके बाद उनके रहन-सहन के स्तर में गिरावट दिखाई देती है।

दूसरा, चूंकि मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक ब्याज दरें घटकर ऋणात्मक हो जाती हैं इसलिए बचत के वास्तविक मूल्य में हास होता है और बचत पर होने वाली आय मूल्य वृद्धि से हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाती है।

तीसरा, आर्थिक कारोबारी अपने उपभोग तथा निवेश के बारे में कोई भी निर्णय अपनी मौजूदा और संभावित

आय तथा भावी मुद्रास्फीति दरों की संभावनाओं के आधार पर लेते हैं। लगातार चल रही उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की संभावनाओं में उलटफेर कर देती है और कीमतों की अस्थिरता से उपजे संशय के कारण व्यक्ति अपने खर्च में कोई कटौती नहीं करता है तथा कंपनियां अपने निवेश में कोई कमी नहीं करती हैं। नतीजतन अंत में आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है।

चौथा, यदि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि दूसरे देशों की तुलना में तेज रफ़्तार से होती है तो हमारे घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम पड़ जाती है जिसका आर्थिक विकास, रोजगार तथा भुगतान संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

पांचवा, उच्च मुद्रास्फीति असमानता को और भी बदतर बनाती है क्योंकि आय का मनमाना पुनः वितरण किया जाता है जहाँ गरीब को सबसे अधिक सहन करना होता है और अमीर मुद्रास्फीति से बच सकते हैं।

अंततः, मुद्रास्फीति को कम करने के नीतिगत उपायों के अपने बाह्य प्रभाव और आनुसंगिक कीमतें होती हैं जिनके परिणामस्वरूप छोटे और मध्यम स्तर पर कुल मांग में कमी आ जाती है।

मुद्रास्फीति का गतिशास्त्र

मिल्टन फ्रीडमैन का एक मशहूर कथन है, “मुद्रास्फीति सर्वदा और सर्वत्र एक मौद्रिक परिघटना होती है।”³ ऐसा माना जाता है कि अल्पकालिक मुद्रास्फीति का गतिशास्त्र ज्यादातर मांग-पूर्ति की स्थितियों पर निर्भर होता है तथा मौद्रिक विस्तार अंततः मुद्रास्फीति की स्थिति को प्रभावित करता है। मौद्रिक विस्तार का कारण लगातार उच्च राजकोषीय घाटा और मुद्राकरण के द्वारा उसके वित्तपोषण की जरूरत हो सकती है। फलतः उच्चस्तरीय मौद्रिक वृद्धि के कारण एक लम्बे समय तक लगातार अतिरिक्त मांग की स्थिति पैदा हो जाती है जब कि उत्पादन और

उत्पादकता से उसका कोई मेल नहीं बैठता। दूसरी तरफ़ पूर्ति की स्थितियां मुद्रास्फीति की गतिकी पर अल्पकालिक रूप से तीव्र प्रभाव डालती हैं।

हमारी तेजी से उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और सभावगत विलक्षणता के कारण मुद्रास्फीति के निर्धारण में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्दर्शी प्रकृति में बदलाव होता रहा है। आम तौर पर सभी क्षेत्रों की गतिविधियां कमोबेश वैश्विक कारकों से प्रभावित हुई हैं। चाहे वह पण्यों में व्यापार, सेवाओं का प्रावधान हो या वित्तपोषण की स्थितियां हों या उपभोक्ता की पसंदा अभी की स्थिति यह है कि वैश्विक स्तर पर पण्य की कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव तुलनात्मक रूप से ढेर सारी वस्तुओं की घरेलू कीमतों पर अधिक पड़ता है - यह स्थिति 1970 और 1980 के दशकों के मुकाबले एक आमूल-मूल बदलाव की तरफ इशारा करती है जब कच्चे तेल की कीमतें ही विश्व स्तर पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक हुआ करती थीं।

वैश्विक तथा घरेलू कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए थोक मूल्य सूचकांक श्रेणी को चार पण्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिनके व्यवहार में अंतर होता है (चार्ट 1)।

पहला, *खाद्य वस्तुएं जिनमें तिलहन उत्पाद शामिल नहीं हैं (डब्ल्यूपीआई में मूल्यगार : 24.2 प्रतिशत)* : इस समूह के पण्यों की कीमतें ज्यादातर घरेलू कारकों से निर्धारित होती हैं और पूर्ति में कमी की स्थिति में आयात के चलते उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी प्रभावित होती हैं।

दूसरा, *तिलहन तथा उनके उत्पाद (डब्ल्यूपीआई में मूल्यगार : 6.8 प्रतिशत)* : तुलनात्मक रूप से इस छोटे पण्य समूह के कारण भी हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में अचानक और प्रायः तेज उठान आता रहा है क्योंकि संरचनात्मक कमी है और, खाद्य तेलों की लगभग एक-तिहाई घरेलू खपत की पूर्ति आयात से होती है।

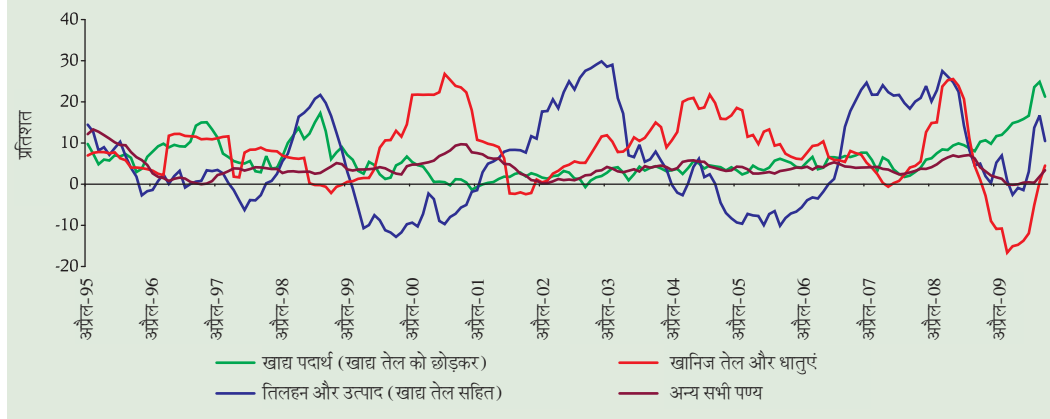
³ मिल्टन फ्रीडमैन (1963) : इम्प्लोशन : कॉजेस एण्ड कांसी क्वेंसेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, न्यूयॉर्क

भाषण

भारत में मुद्रास्फीति का गतिशास्त्र : मुद्दे और चिंताएं

दीपक मोहंती

चार्ट 1: डब्ल्यूपीआई पण्य समुह के लिए मुद्रास्फीति दर



तीसरा, *खनिज तेल एवं धातुएं (डब्ल्यूपीआई में मूल्यगार : 15.3 प्रतिशत)* : इस समूह के पण्यों की कीमतों का निर्धारण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के द्वारा होता है और हाल के वर्षों में हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में अनिश्चितता का कारण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव थे।

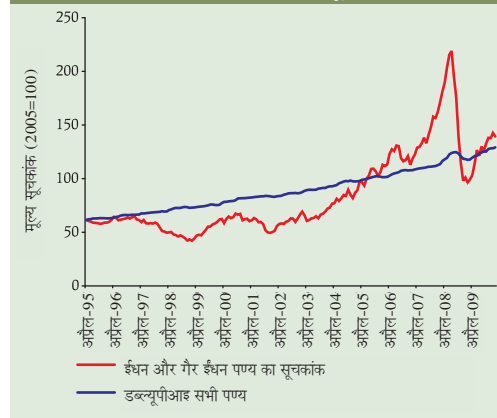
चौथा, *अन्य पण्य (डब्ल्यूपीआई में मूल्यगार : 53.7 प्रतिशत)* : ये शेष पण्य जो मुख्य रूप से विनिर्मित उत्पाद हैं, डब्ल्यूपीआई वर्ग के आधे से अधिक पण्य हैं और उनकी कीमतें अन्य तीन समूहों के पण्यों की कीमतों से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रही हैं।

अनुभवजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि उपर्युक्त चार समूहों के बीच एक तिमाही के भीतर खनिज तेलों तथा धातुओं की कीमतों का प्रभाव अन्य पण्य समूह की कीमतों पर पड़ जाता है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव अन्य पण्यों पर पड़ने में अपेक्षाकृत अधिक समय अर्थात् तकरीबन एक वर्ष लग जाता है।

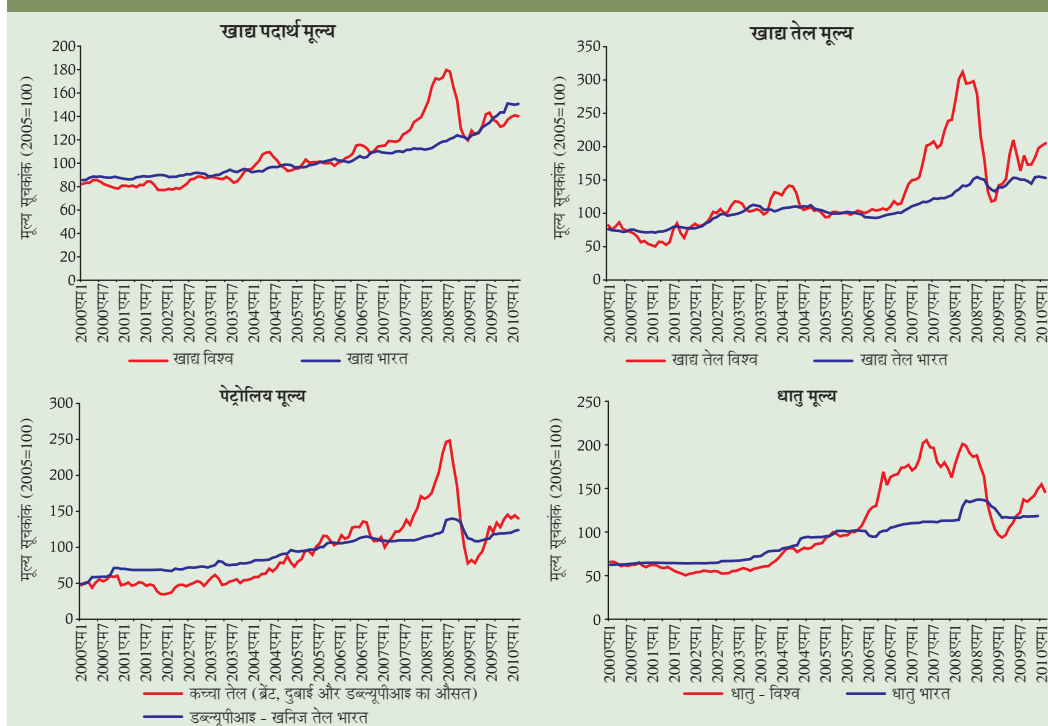
घरेलू तथा वैश्विक पण्य कीमतों में परिवर्तन की तुलना से निम्नलिखित बातें खुलकर सामने आती हैं। पहली, कीमतों में परिवर्तन की दिशा एक समान रही है

लेकिन सामान्य तौर पर वैश्विक पण्य कीमतों में परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थिर रहे हैं। इस बीच वर्ष 2007 और 2008 के दौरान यह अस्थिरता और भी तीव्र रही (चार्ट 2)। दूसरी, धातुओं की कीमतें अपनी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के काफी करीब रही हैं। तीसरी, पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतें अपनी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम अस्थिर रही हैं जिससे इस समूह की नियंत्रित कीमतों का पता चलता है। चौथी, वर्ष 2007 तथा 2008 की वैश्विक वृद्धि को छोड़ दें तो घरेलू खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि अधिक रही है जिससे संरचनात्मक और घरेलू कारकों का पता चलता है (सारणी 3)।

चार्ट 2: समग्र पण्य मूल्य सूचकांक की गति: वैश्विक और घरेलू



चार्ट 3: चुनिंदा पण्यों के वैश्विक और घरेलू मूल्यों की गति



सारणी 3: पण्य मूल्य परिवर्त: वैश्विक और घरेलू

पण्य समुह	(प्रतिशत)			
	वार्षिक वृद्धि दर (दीर्घ-रैखिक प्रवृत्ति: 1993-2009)		घट-बढ़ का गुणांक	
	भारत	विश्व	भारत	विश्व
1	2	3	4	5
सभी पण्य	4.9	7.3	0.30	1.69
<i>जिसमें से:</i>				
खाद्य पदार्थ (खाद्य तेलों को छोड़कर)	4.4	1.8	0.61	2.85
तिलहन और उत्पाद (खाद्य तेलों को छोड़कर)	4.5	1.5	1.82	4.60
खनिज तेल	11.0	12.4	0.92	1.79
धातुएं	6.4	6.8	0.84	2.88

टिप्पणी: वैश्विक मूल्यों के लिए आइएमएफ पण्य मूल्य डेटाबेस से संगत डब्ल्यूपीआइ समुह के निकटवर्ती मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।

भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतें मुख्य रूप से घरेलू मांग-पूर्ति के कारकों और घरेलू मूल्य नीति से निर्धारित होती हैं। खाद्य तेलों तथा दालों जैसे कुदक पण्यों को छोड़कर भारत की खाद्य वस्तुओं की भारी मांग के एक बड़े हिस्से की पूर्ति घरेलू उत्पादन से हो जाती है। खाद्य तेलों और दालों की जरूरतें क्रमशः 35 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत आयात से पूरी की जाती हैं। कभी-कभार कमी पड़ने पर हमारे देश को गेहूं और चीनी भी आयात करना पड़ा है। हालांकि हम इन पण्यों के सामान्य तौर पर निर्यातक हैं (सारणी 4)। भारत द्वारा इन पण्यों का कभी-कभार आयात करने पर वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि आयात की मांग बहुत बड़ी होती है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि आयात के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट हो।

भारत में कृषि उत्पाद की कीमतों का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व विभिन्न पण्यों की खरीद के लिए सरकार

भाषण

भारत में मुद्रास्फीति
का गतिशास्त्र :
मुद्दे और चिंताएं
दीपक मोहंती

**सारणी 4: भारत में प्रमुख खाद्य मदों में उत्पादन -
उपभोग में अंतर**

(मिलियन टन)					
	चावल	गेहूँ	दालें	चीनी	तिलहन
1	2	3	4	5	6
2004-05	2.3	-4.2	-0.9	-4.1	-4.6
2005-06	6.7	-0.4	-1.0	0.7	-1.9
2006-07	6.6	2.4	-1.6	8.3	-6.2
2007-08	6.2	2.2	-2.6	5.1	-4.0
2008-09 अ.	6.0	9.8	-2.2	-8.1	-4.7
2009-10 अ.	-2.8	2.1	-2.3	-7.5	-6.0

अ. : अनुमानित (-): कमी दर्शाता है।
स्रोत: कृषि मंत्रालय और अमरीकी कृषि विभाग से प्राप्त आँकड़ों के माध्यम से आकलित।

द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रहा है। वर्ष 2007-08 से न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेज वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में उछाल के तेवर आए हैं (सारणी 5)।

खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी के कारण भी खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार पिछले चार दशकों के दौरान प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध अनाज और

**सारणी 5: कृषिगत पण्य - एमएसपी और
डब्ल्यूपीआइ में घट-बढ़**

(प्रतिशत)			
पण्य		औसत वार्षिक वृद्धि दर	
		2003-04 से 2006-07	2007-08 से 2009-10
1	2	3	4
धान	एमएसपी	2.3	18.3
	डब्ल्यूपीआइ	2.0	10.9
गेहूँ	एमएसपी	5.1	14.4
	डब्ल्यूपीआइ	5.5	6.7
तूर	एमएसपी	1.7	18.0
	डब्ल्यूपीआइ	3.9	26.3
मूग	एमएसपी	3.4	23.2
	डब्ल्यूपीआइ	11.3	13.2

एमएसपी : 2009-10 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डब्ल्यूपीआइ फरवरी 2010 तक का औसत है।
स्रोत : कृषि मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय।

दालें आज उपलब्ध मात्रा से अधिक थीं। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 1960 तथा 1970 के दशक में 447 ग्राम थी। 1980 के दशक में यह बढ़कर 459 ग्राम और 1990 के दशक में 478 ग्राम हो गई थी। लेकिन उसकी मात्रा 2000-08 के दौरान घटकर 446 ग्राम और वर्ष 2008 के दौरान तो वह और घटकर 436 ग्राम हो गई थी। चालू वर्ष के दौरान देश के अधिकांश भागों में गंभीर सूखे के कारण महसूस किया जा रहा है कि खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में और गिरावट आई है। विशेष रूप से दालों के मामले में स्थिति और भी चिंताजनक है। 1950 के दशक की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दालों की उपलब्धता 60-70 ग्राम से घटाकर वर्तमान समय में 30 ग्राम हो गई है।

हाल के वर्षों में मांग के मोर्चे पर भारत का एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन ग्रामीण मांग में आई उछाल के रूप में दिखाई दिया है जिसकी अब कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार संपूर्ण खपत में ग्रामीण खपत की हिस्सेदारी वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 58 प्रतिशत थी। संपूर्ण ग्रामीण खपत में गैर-कृषि क्षेत्र की खपत की प्रतिशतता लगभग 55-60 है। जब कि कृषि क्षेत्र की मांग मौसम की लुकाछिपी के प्रति अधिक संवेदनशील है वहीं ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं के अंतर्गत परिव्यय में वृद्धि के द्वारा अधिक ध्यान देने के कारण हाल के वर्षों में गैर-कृषि ग्रामीण क्षेत्र ने अधिक स्थिरता प्रदान की है।

हमारे आर्थिक विकास के मौजूदा चरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि में इजाज़ा और आय के स्तरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं के लिए मांग बढ़ेगी। भारत की प्रगति तथा उत्पादकता में जनसांख्यिकीय लाभों का योगदान तो है ही बल्कि उसके कारण खपत के स्तर ऊँचे भी उठे हैं। विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की खपत में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार उच्च खपत करने वाले 15-59 के आयु वर्ग के व्यक्तियों की हिस्सेदारी भारत की कुल

जनसंख्या में 65 प्रतिशत है। इस वर्ग की मांग वर्ष 2040 तक सबसे अधिक रहेगी।

इस प्रकार प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की कम मात्रा तथा तिलहन और दालों जैसे मुख्य कृषि पण्यों में संरचनात्मक कमी के साथ-साथ बढ़ती हुई मांग के कारण खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति अपने ऊँचे स्तर पर बनी रही है। इस प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण बल मिला है।

निष्कर्ष

मुद्रास्फीति में हुई हाल की वृद्धि ने इस चिंता को जन्म दिया है कि पूर्ति आधारित वृद्धि का प्रभाव फैलकर सामान्यीकृत मुद्रास्फीति की प्रक्रिया के भीतर पहुँच जाएगा। सुदीर्घ उच्च मुद्रास्फीति भले ही वह पूर्ति पक्ष से उत्पन्न हुई हो, के कारण मुद्रास्फीति की संभावनाओं में इजाफा होगा और सामान्य कीमतों में भी वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति की नियंत्रित संभावनाओं के कारण दीर्घकालिक वित्तीय योजना काफी जटिल हो जाती है जिसका भव्य में निवेश और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुद्रास्फीति की संभावनाओं को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है ताकि उपभोक्ता उम्मीद से ज्यादा मुद्रास्फीति की अल्प अवधि के जवाब में दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की संभावनाओं को निर्धारित न करें।

मुद्रास्फीति जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा समय उसे लौटकर अपनी पिछली प्रवृत्ति में आने में लगता है। पूर्ति के एक पैकेज द्वारा मुद्रास्फीति दर की अपने संतुलन

स्तर में धीमी वापसी को ‘‘मुद्रास्फीति की निरंतरता’’ के रूप में जाना जाता है। अभीष्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए मौद्रिक नीति समायोजन की गति का निर्धारण करने में उसकी भूमिका अहम होती है। हमारे संदर्भ में अनुभवजन्य विश्लेषण से मुद्रास्फीति की निरंतरता का काफी ऊँचा स्तर विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं और खाद्य तेलों के समूहों के मामले में दिखाई देता है। इससे तयशुदा समय में पूर्ति के मोर्चे पर किए गए उपायों के सक्रिय होने की प्रक्रिया बाधित होती है।

यदि मुद्रास्फीति के बिखराव के फैलकर व्यापक मुद्रास्फीति प्रक्रिया से जुड़े जोखिमों को देखा जाए तो हालांकि पूर्ति पक्ष के कारक चालू मुद्रास्फीति के दबावों पर हावी हैं फिर भी नीतिगत स्तर पर पहल करने की जरूरत है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने संभावित चलनिधि को कम करते हुए अक्टूबर 2009 में विस्तारवादी मौद्रिक नीति से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जनवरी 2010 तक लाया गया जब बैंकों के प्रारक्षित चलनिधि अनुपातर (सीआरआर) में 75 आधार अंकों तथा मार्च 2010 में नीतिगत रिवर्स रिपो और रेपो दरों में से प्रत्येक में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई। एक तरफ़ जब यह जरूरी हो कि मौद्रिक नीति की कार्रवाई से मुद्रास्फीति की संभावनाओं को नियंत्रित किया जाए तो दूसरी तरफ़ यह भी जरूरी है कि संरचनात्मक पूर्ति की बाधाओं के मुद्दे पर, खास तौर से कृषि क्षेत्र में, ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक है ताकि ये अंत में एक बाध्यकारी समस्या न बन जाएं और जिससे मुद्रास्फीति प्रबंधन का काम कठिनतर बन जाए।